ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

लॉक डाउन से बस प्रदूषण हुआ कम पर ग्रीनहाउस गैसें लहरा रहीं परचम

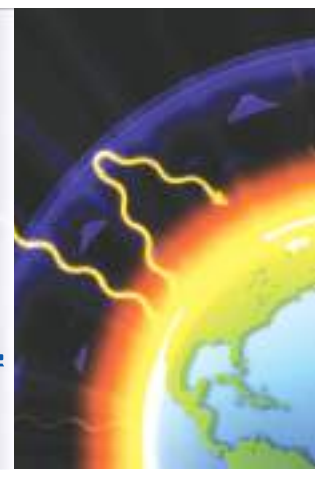

रविवारीय, 29नवंबर - 05 दिसंबर 2020 वर्ष- दो, अंक-17, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

कृषि कानून पर मची रार

मनोज कुमार शर्मा

जब नरेन्द्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बन कर संसद की कैंटीन में भोजन करने पहुंचे और बिल के भुगतान के साथ ही बिल पर लिखा कि अन्नदाता सुखी रहे तो उनकी वह लिखी गयी बात बहुत चर्चित हुयी थी।

आज दूसरे कार्यकाल में उनकी सरकार ने अन्नदाता के लिये नये कृषि कानून बनाये हैं तो देशव्यापी शोर मचा हुआ है। विपक्ष इसमें दर्जनो खामियां निकाल रहा है वहीं कई कृषि विशेषज्ञ भी इसे दोषपुर्ण मान रहे हैं। तो क्या नया कृषि कानून पूर्णतः किसानों के लिये अहितकर है? या इसमें किसानों के लिये अच्छी चीजें भी हैं? इस बात को लेकर पूरा देश बंटा हुआ है।

भारत में कृषि का सेक्टर अपने आप में एक अबूझ पहेली है। लेकिन एक बात सत्य है कि देश का किसान सदैव गरीब और कमजोर ही रहा है और हमारे कथा कहानियों में भी किसान एक गरीब प्राणी के तौर पर ही उभरता है। आजादी के बाद किसी भी केंद्र सरकार ने किसानों के लिये कोई बड़े बदलाव का कदम नहीं उठाया, सिर्फ किसानों की तारीफ कर उन्हें अन्नदाता बता कर अंततः उपेक्षित कर दिया गया। वर्तमान सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिये कुछ बड़े कदम उठाये हैं और बजाय इसका विरोध करने के अगर सरकार, कृषि विशेषज्ञ, किसानों और पिछले आंकड़ों को उठा कर एक मंथन किया जाये तो सकारात्मक फल प्राप्त हो सकता है। वर्तमान में कृषि कानून पर विरोध में पंजाब के किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया है और अन्य राज्यों के किसान इसमें शामिल नहीं है। पर फिलहाल कृषि कानून पर विरोध किसी अच्छे निष्कर्ष प्रप्ति के प्रयास के बजाय राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है।

कृषि कानून के इन बातों पर है विरोध

विरोध कर रहे किसानों , विपक्ष और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान कृषि कानून में एमएसपी पर खरीद की गारंटी नहीं है। सरकार इस पर सिर्फ जबानी आश्वासन तो दे रही है, पर अंततः उसकी मंशा एमएसपी खरीद को बंद कर देने की ही है। इसके बंद होने से किसानों को मजबूरी में अपनी उपज औने पौने दामों में बेचनी पड़ेगी।

कांट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर विरोध करने वालों का कहना है कि इसमें कांट्रैक्ट करने वाली कंपनियां सीधे सादे किसानों के साथ ठगी करेंगी, किसानों को अपने तय किये गये कम कीमत पर उपज बेचने को मजबूर करेंगी और विवाद होने पर ये शातिर कंपनियां किसानों को कानूनी मकड़जाल में उलझा देंगी। अंततः किसान ही ठगा जायेगा।

नये कानून के अनुसार कालाबाजारी और जमाखोरी की छूट मिलेगी। चुंकि अब स्टॉक करने पर कोई पाबंदी भी नहीं रहेगी तो ऐसे में व्यापारी स्टॉक कर जमाखोरी को ही बढायेंगे। योगेंद्र यादव ने तो कृषि कानून में सात खामियां गिनवा दी हैं और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि इस कानून से अंततः ऐसी नौबत आ जायेगी कि गरीबों को मिलने वाला सस्ता अनाज भी बंद हो जायेगा।

सोशल मीडिया पर कृषि विशेषज्ञों की भरमार

देश में किसी भी विवाद में सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफार्म बन जाता है। वर्तमान कृषि कानून पर केंद्र सरकार के समर्थक और विरोधी भी आपस में सोशल मीडिया पर भिड़े हुये हैं। विरोधी जहां इसकी खामियों के पक्ष में एक से एक निष्कर्ष और आशंकायें प्रस्तुत कर रहे हैं वहीं सरकार के समर्थक नये कृषि कानून से सिर्फ दलालों और बिचौलियों को नुकसान होने की बात कह रहे हैं।

हालांकि ये एक सकारात्मक बात है कि विरोध और समर्थन के कारण ही देश अब तक उपेक्षित रहे कृषि क्षेत्र के बारे में पढ रहा है, जानकारी एकत्र कर रहा है।

कानून को लेकर फैलाया जा रहा है भ्रमःप्रधानमंत्री

किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने कहा, कानून को लेकर फैलाया जा रहा है । नए कृषि कानून को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण दिए गए हैं। पहले मंडी के बाहर हुए लेनदेन ही गैरकानूनी थे। अब छोटा किसान भी, मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों को कितना लाभ हो रहा है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण चंदौली का काला चावल है। जिसकी 300 रुपये प्रति किलो तक बिक्री हो रही है। इसे विदेशी बाजार भी मिल गया है। ये चावल चंदौली के किसानों के घरों में समृद्धि लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं, तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लगते हैं। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल हैं, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है। मुझे विश्वास है, आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर, अपनी आय बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री एवं शिबू सोरेन ने शहीद सोबरन सोरेन के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी

★ झारखंड को संवारने का वक्त आ गया है

★ जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार, लॉकडाउन में दिखी सरकार की प्रतिबद्धता

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि शहीद सोबरन सोरेन जी के शहादत दिवस के पर बरलंगा के लुकैयाटांड में हर साल की भांति इस साल भी एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह पवित्र भूमि को झारखंड के हर एक व्यक्ति जानते हैं। यह वही भूमि है, जहां से इस अलग झारखंड राज्य के लिए, मूलवासी-आदिवासी के लिए, जल, जंगल, जमीन के लिए क्रांतिकारी आवाज बुलंद हुई थी। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने शहीद सोबरन सोरेन के 63वीं शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही।

क्रांतिकारी आवाज की यादें ताजा करती हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शहीद भूमि पर हमें मार्गदर्शन करने वाले हमारे पूर्वज मेरे दादाजी सोबरन सोरेन का 63वं शहादत दिवस है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह दिवस हम सभी को क्रांतिकारी आवाज के प्रारंभ की यादें ताजा करती हैं। यहां की खूबसूरत वादियों से क्रांतिकारी आवाज के आज कई मायने हैं। यहां से उठाई गई बुलंद आवाज व्यर्थ नहीं गया। इसी क्रांतिकारी आवाज से आज हम अपना वजूद बचा पाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग झारखंड राज्य निर्माण की लंबी लड़ाई पूर्वजों ने लड़ी। आज इस अवसर पर झारखंड राज्य के जन्मदाता दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी हमारे साथ मौजूद हैं।

"थर्ड एडिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो रि-इन्वेस्ट" का कार्यक्रम हुआ संपन्न

रांची : 26 नवंबर 2020 से 28 नवंबर 2020 तक वर्चुअल प्लेटफार्म पर आयोजित किया गया गए "थर्ड एडिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो रि-इन्वेस्ट" कार्यक्रम में मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार, मिथिलेश कुमार ठाकुर एनआईसी- गढ़वा से शामिल हुए। राज्य के किसानों को सोलर पंप की समस्या से उबारने के लिए माननीय मंत्री ने पीएम कुसुम योजना का कार्य ज़ेडा को देने की .केंद्र सरकार से की मांग की गयी है ।कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाने में आने वाली समस्याओं को लेकर कहा कि यहां के लगभग 45000 किसानों ने उक्त योजना में अपने हिस्से की राशि जमा कर दी है साथ ही राज्य सरकार ने भी इसमें 70 करोड़ रुपए रिलीज कर दी है परंतु किसानों को अब तक इसका लाभ नहीं दिया गया है।

फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार

संवाददाता

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए निम्नलिखित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है, अब ये ट्रेनें दिनांक 12 दिसंबर 2020 तक चलेंगी।

ट्रेन संख्या 02835 हटिया - यशवंतपुर (साप्ताहिक) फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दिनांक 30/12/2020 तक प्रत्येक मंगलवार हटिया से चलेगी।

ट्रेन संख्या 02836 यशवंतपुर - हटिया (साप्ताहिक) फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दिनांक 30/12/2020 तक प्रत्येक शुक्रवार यशवंतपुर से चलेगी।इन ट्रेनों में एस एल आर के 02 कोच, द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास के 15 कोच, वातानुकूलित 3-टियर के 04 कोच, वातानुकूलित 2-टियर का 01 कोच, कुल 22 कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 02812 हटिया - लोकमान्य तिलक टर्मिनल (साप्ताहिक) फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दिनांक 30/12/2020 तक प्रत्येक शुक्रवार हटिया से चलेगी।

ट्रेन संख्या 02811 लोकमान्य तिलक टर्मिनल - हटिया (साप्ताहिक) फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दिनांक 30/12/2020 तक प्रत्येक रविवार लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलेगी।इन ट्रेनों में जनरेटर यान के 02 कोच, सामान्य श्रेणी के 04 कोच, द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास के 07 कोच, वातानुकूलित 3-टियर के 06 कोच, वातानुकूलित 2-टियर के 02 कोच, रसोई यान का 01 कोच, कुल 22 कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 08626 हटिया - पूर्णिया कोर्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दिनांक 30/12/2020 तक प्रतिदिन हटिया से चलेगी। ट्रेन संख्या 08625 पूर्णिया कोर्ट - हटिया फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दिनांक 30/12/2020 तक प्रतिदिन पूर्णिया कोर्ट से चलेगी। इन ट्रेनों में एस एल आर के 02 कोच, सामान्य श्रेणी के 11 कोच, द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास के 05 कोच, वातानुकूलित 3-टियर का 02 कोच, वातानुकूलित 2-टियर का 01 कोच, कुल 21 कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 08624 हटिया - इस्लामपुर स्पेशल ट्रेन दिनांक 30/12/2020 तक प्रतिदिन हटिया से चलेगी।

ट्रेन संख्या 08623 इस्लामपुर - हटिया स्पेशल ट्रेन दिनांक 30/12/2020 तक प्रतिदिन इस्लामपुर से चलेगी। इन ट्रेनों में जनरेटर यान के 02 कोच, सामान्य श्रेणी के 04 कोच, द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास के 09 कोच, वातानुकूलित 3-टियर के 05 कोच, वातानुकूलित 2-टियर का 01 कोच, वातानुकूलित फर्स्ट क्लास का 01, कोच कुल 22 कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 02803 रांची - हावड़ा स्पेशल ट्रेन दिनांक 30/12/2020 तक प्रतिदिन हटिया से चलेगी।ट्रेन संख्या 02804 हावड़ा - रांची स्पेशल ट्रेन दिनांक 30/12/2020 तक प्रतिदिन हावड़ा से चलेगी। इन ट्रेनों में जनरेटर यान के 02 कोच, द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास के 11 कोच, वातानुकूलित 3-टियर के 04 कोच, वातानुकूलित 2-टियर के 02 कोच, वातानुकूलित फर्स्ट क्लास का 01 कोच, कुल 20 कोच होंगे।

रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में नामांकन प्रारंभ

रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में नामांकन प्रारंभ हो गया है। इच्छुक छात्र नामांकन के लिये आवेदन एवं अन्य जानाकारियों सहित प्रोस्पेक्टस विभाग के वेबसाइट http://djmcru.org.in/ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या मोराबादी स्थित विभागीय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

विभाग के वेबसाइट पर नामांकन के लिये सभी अर्हताओं की जानकारी विस्तार से उपलब्ध है।रांची विवि के स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार में नामांकन के लिये किसी भी विषय से 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक पास होना अनिवार्य है।

रांची विवि में लोक प्रशासन विषय में नामांकन प्रारंभ

रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग (मोराबादी कैंपस) में संचालित लोक प्रशासन (public administration) विषय में नामांकन शुरू हो चुका है । किसी भी विषय से स्नातक उतीर्ण विद्यार्थी विभाग से फॉर्म प्राप्त कर इसमें direct admission ले सकते हैं । यह जानकारी डॉ. एल. के. कुंदन (निदेशक) ने दी है । अधिक जानकारी के लिए मोबाइल संख्या 9431360268 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

मेकॉन को सेल से दो बड़े प्रोजेक्ट का मिला कार्यदेश

संवाददाता :कोरोना काल के इस महामारी में भी स्टील सेक्टर बेहतर कर रहा है। हालिया वर्षों की मंदी से उबर कर अब ये बेहतरी की ओर आगे बढ़ रहा है। मेकॉन लिमिटेड को **पिछले साल की तुलना में बेहतर व्यापार की जताई उम्मीद** भी नए-नए कार्यदेश मिल रहे हैं। ये बातें बुधवार को मेकॉन लिमिटेड की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में कंपनी के महाप्रबंधक (विपणन) श्री आरके पिल्लई ने कही। इस दौरान मुख्य महाप्रबंधक (सी एम एस) श्रीमती आशा विश्वास और वरीय महाप्रबंधक (सी एम एस) श्री संदीप सिन्हा भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष पिछले साल की तुलना में पिछले साल से बेहतर व्यापार की उम्मीद है। श्री पिल्लई ने बताया कि मेकॉन को सेल से दो बड़े कार्यादेश मिले हैं। इसके तहत राउरकेला स्टील प्लांट के कोकओवन बैटरी नंबर दो का पुनर्निर्माण शामिल है। वहीं दूसरे कार्यादेश के भिलाई स्टील प्लांट में कोकओवन बैटरी संख्या सात और आठ का पुनर्निर्माण करना शामिल है। इसके अलावा भी कोल इंडिया को कई अन्य कार्यादेश मिले हैं।

कोर सेक्टर से इतर भी कर रहा काम

प्रेस कांफ्रेंस में श्रीमती आशा विश्वास ने बताया कि इस दौरान अच्छी बात ये रही कि मेकॉन लिमिटेड अपने कोर सेक्टर स्टील एंड मेटल से निकल कर अन्य सेक्टरम में भी काम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि गेल के लिए गैस पाइपलाइन बिछाने के साथ कोल इंडिया के राजमहल और महानदी कोल्फील्ड में कोलहैंडलिंट प्लांट बनाने का काम शामिल है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द इन सबका काम शुरू हो जाएगा।

एमएसएमई को मिलेगा बढ़ावा

वरीय महाप्रबंधक श्री संदीप सिन्हा ने बताया कि मेकॉन के सुदृढ़ होने से न केवल इनसे जुड़े वेंडर्स को लाभ मिलेगा। बल्कि एमएसएमई सेक्टर को भी इससे फायदा होगा। मेकॉन के साथ पहले ही कई मध्यम व लघु उद्यमी रजिस्टर्ड हैं।

रोजगार

देश में मत्स्य विशेषज्ञों की है भारी मांग

आशीष कुमार

आम जनता के भोजन में प्रोटीन युक्त भोजन की भारी मांग को देखते हुए मछली उत्पादन को एक नया आयाम मिला है। हाल के वर्षों में लोगों में देखा गया है कि मटन तथा चिकन के के बदले में मछली की ओर झुकाव बढ़ा है। इसके कारण जहां एक और मछली की मांग बढ़ी है वहीं दूसरी ओर नए लोग मछली पालन की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इसके साथ ही मछली पालन के जो नए तरीके विकसित हुए हैं जैसे कि बायो फ्लॉक तकनीक, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम इत्यादि इनके कारण भी मछली पालन के क्षेत्र में नए लोगों का प्रवेश हुआ है। मछली पालन के लिए बीज की मांग भी बढ़ी है। मछली पालन के साथ-साथ बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी बहुत अधिक संभावना बढ़ी है।

इस क्षेत्र में लोगों की रूचि के बढने और व्यावसायिक रूप लेने के बाद मछली पालन अथवा बीज उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी देने वाले मत्स्य विशेषज्ञों की आवश्यकता भी बढ़ी है और देखा गया है कि देश में जहां एक और लगभग 25000 मत्स्य वैज्ञानिकों की आवश्यकता है वही विभिन्न मात्स्यकी महाविद्यालयों से मात्र 1000 मत्स्य वैज्ञानिकों को प्रतिवर्ष तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही मत्स्य पालन के क्षेत्र में अनुभवी तकनीशियनों की भी भारी मांग है। इस पर देश के नीति निर्धारकों के द्वारा विभिन्न स्तर पर चिंता व्यक्त की गई है जो कि हाल के समाचार पत्रों में परिलक्षित हुआ है। इसलिए अभी आवश्यकता है कि राज्य स्तर पर हैचरियो के संचालन के लिए, मत्स्य बीज के उत्पादन के लिए नर्सरीयों के प्रबंधन के लिए, केज कल्चर और पेन कल्चर के द्वारा मछली उत्पादन में तकनीकी सहायता के लिए, बयोफ्लोक और आर ए एस के संचालन के लिए, मछलियों के परिवहन के लिए और इस संबंध में जो नए-नए तरीके विकसित हो रहे हैं उनकी जानकारी किसानों को देने के लिए मत्स्य वैज्ञानिकों की आवश्यकता का आकलन किया जाए और उसे कैसे पूरा किया जाए इस पर नीति निर्धारण किया जाए क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि यह क्षेत्र ना केवल ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजित कर रहा है बल्कि मछलियों के निर्यात से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहा है।

सरकार के द्वारा मत्स्य पालन का मंत्रालय अलग करना और प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू करना दो महत्वपूर्ण कदम है जो इस दिशा में निश्चित रूप से सहायता करेगा। अतः सभी राज्यों को अपने राज्य में उपलब्ध मत्स्य विशेषज्ञों की संपदा का आकलन करना और कैसे उसमें वृद्धि की जाए इस पर विचार करना समय की मांग है। इससे ना केवल रोजगार सृजित होगा बल्कि किसानों को महत्वपूर्ण सलाह समय पर मिलेंगे और वे अपने प्रयास में सफल होंगे।

लेखक सेवानिवृत उपनिदेशक (मत्स्य विभाग) हैं Ph. 9430783037

email:coomar2012@gmail.com

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

ईमानदारी से मंथन और निदान की आवश्यकता

नये कृषि कानून पर घमसान मचा हुआ है।इन नये कानूनों पर सरकार का मकसद है कि किसान की आमदनी बढ़े, उनकी समृद्धि बढ़े। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश आए, नई टेक्नोलॉजी आए। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अधिक से अधिक निवेश करे। सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र खेती में उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक में न केवल निवेश बढ़ाए, बल्कि नई तकनीक का भी इस्तेमाल करे। यह दावा किया जा रहा है कि इससे किसानों को अपनी उपज की ऊंची कीमत मिलेगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी। हम सभी यही तो चाहेंगे कि यह सच हो, क्योंकि किसान भी सालों से इसी बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी आमदनी बढ़े और उनकी उपज की सही कीमत उन्हें मिले।

भारत में कृषि कभी भी किसी केंद्र सरकार की प्राथमिकता में नहीं रहा। इसे एक ऐसा सेक्टर मान लिया गया जो गिरते पड़ते स्वयं किसी न किसी तरह से चलते रहता है। यही कारण है कि देश में सात दशकों से अन्नदाता की महिमा और स्तुति तो रस्मि तौर पर गायी जाती रही, पर किसी भी सरकार ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिये कोई ठोस कदम कभी नहीं उठाया। उल्टे पूर्ववर्ती सरकारों ने किसानों को ऋण के जाल में फंसा कर उनकी जमीन तक बिकवा दी।

वर्तमान सरकार के कृषि कानूनों को लेकर विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, पर बेहतर होता कि सीधे विरोध के बजाय इस पर सभी मिल कर नये कानूनों की खुबियों खामियों पर विचार करते और इसमें दिक्कत वाली बातों का निदान ढूंढते। अन्यथा अंधविरोध से एक अच्छी पहल राजनीति की भेंट चढ जायेगा और अंततः किसान ही ठगा जायेगा।

लेकिन यह एक बड़ी चुनौती है। अब तक यह बताया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर ही किसान को सही कीमत दे सकता है और किसान को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इसके दो तीन पहलुओं पर बात करनी जरूरी है। यह बात किसानों को भी समझनी चाहिए, एकेडमिशन हो या छात्र हो, बल्कि देश के हर नागरिक को भी समझनी चाहिए और खासकर नीतियां बनाने वाले लोगों को भी समझनी चाहिए।अगर हम दुनिया भर में देखें तो ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि मार्केट रिफॉर्म्स की वजह से किसानों को फायदा हुआ हो। क्योंकि अमेरिका और यूरोप में कई दशकों पहले ओपन मार्केट के लिए कृषि उत्पादों को खोल दिया गया था। और अगर ओपन मार्केट इतनी अच्छी होती और किसानों को फायदा दिया होता तो अमीर यानी विकसित देश अपने यहां कृषि को जीवित रखने के लिए भारी सब्सिडी क्यों देते हैं?

हालांकि इन यूरोपीय तथ्यों से नये कृषि कानून को लेकर हताश होने की भी आवश्यकता नहीं है।भारत की स्थिति अलग होती है। हमें यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वर्तमान सरकार ने किसान हित में किसी अच्छे बदलाव का सोच कर ही यह कदम उठाया होगा? आवश्यकता है इस पर ईमानदार मंथन, किसानों से वार्ता की। अन्यथा आजादी के बाद कीअब तक की सरकारों ने तो इतना भी नहीं किया था।

क्वांटम डॉट सोलर सेल की क्षमता को बढ़ा कर 11.53 फीसदी अधिक बिजली प्राप्त की

क्वांटम डॉट सौर सेल द्वारा सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पन्न करने की चुनौतियों को हल करके इसकी क्षमता को 11.53 फीसदी तक बढ़ाता है। एक नई तकनीक जो क्वांटम डॉट सौर सेल की दक्षता में सुधार कर उस–ाकी क्षमता को बढ़ाकर 11.53 फीसदी कर सकती है। यह सौर सेल द्वारा सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पन्न करने की चुनौतियों को हल करके इस–ाकी क्षमता को बढ़ाता है।

इससे पहले किए गए एक अध्ययन में बताया गया था कि जैविक सौर सेल में ऊर्जा की हानि होती है। जो प्रकाश को पूरी तरह से बिजली में नहीं बदल सकता है। इसको लेकर टीम की योजना थी कि ऊर्जा का नुकसान कम हो साथ ही बढ़े हुए चार्ज जनरेशन क्षमता को मिलाकर नई सामग्रियों को डिजाइन किया जाए, जो अब क्वांटम डॉट सौर सेल के रूप में सामने आई है। यूएनआईएसटी के स्कूल ऑफ एनर्जी एंड केमिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर सुंग–योन जंग के नेतृत्व में एक शोध दल ने एक फोटोवोल्टिक उपकरण विकसित किया है जो कार्बनिक पॉलिमर का उपयोग करके क्वांटम डॉट सौर सेल की क्षमता को बढ़ाता है। सौर सेल एक विशेषता का उपयोग करती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों और होल को अवशोषित परत में उत्पन्न किया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों और होल तब सेल के माध्यम से चलते हैं और होल को भरते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों के होल की वह गति है जो बिजली उत्पन्न करते हैं। इसलिए कई इलेक्ट्रॉन के होल में जोड़ी बनाना, उनका घूमना एक अच्छे सौर सेल के डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन एडवांस्ड एनर्जी मैटेरियल्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शोध दल ने क्वांटम डॉट सोलर सेल्स के एक तरफ के ऑर्गेनिक होल ट्रांसपोर्ट मटीरियल (एचटीएम) को बेहतर एक्सट्रैक्ट और ट्रांसपोर्ट होल में बदल दिया। इसका कारण यह है कि नए बने कार्बनिक पॉलिमर न केवल बेहतर होल बनाने की क्षमता रखता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों और होल को पुनः साथ जुड़ने से रोकता है। इससे शोध दल 11.53 फीसदी बिजली प्राप्त करने में सफल रहे।

31 दिसंबर तक आरओ का इस्तेमाल बंद करना होगा: एनजीटी

अधिसूचना जारी करने को कहा था
देश में रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) तकनीक के उपयोग के कारण पानी की अत्यधिक हानि हो रही है। इस मामले पर 13 जुलाई 2020, को एनजीटी के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति सोनम फिंटसो वांग्दी की दो सदस्यीय पीठ में सुनवाई हुइ थीं।

अदालत ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को 20 मई, 2019 के अपने आदेश में एनजीटी द्वारा निर्धारित तरीके से आरओ के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने को कहा था, पर ऐसा नहीं किया गया। इस देरी पर अदालत ने मंत्रालय से जवाब मांगा। एक वर्ष बीतने के बाद भी, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने लॉकडाउन के कारण समय बढ़ाने की मांग की थी। अदालत ने निर्देश दिया कि आवश्यक कार्रवाई अब 31 दिसंबर, 2020 तक पूरी की जानी चाहिए।

भारत में कोयला बिजली परियोजनाओं को मिलने वाला बैंक लोन घट रहा है

कोयले के लिए फाइनेंस मिलने में गिरावट का मतलब है कि वित्तीय संस्थानों को कोयले में निवेश से जुड़े जोखिमों का एहसास होने लगा है।

लगातार दूसरे साल कोयला वित्त पोषण में गिरावट दर्ज की गयी है। एक ताज़ा रिपोर्ट की मानें तो पिछले साल दिए गए ऋणों में से 95 फीसद रिन्युबल ऊर्जा परियोजनाओं के लिए थे और महज़ 5 फ़ीसद ही कोयला बिजली परियोजनाओं के लिए थे। इस तथ्य का ख़ुलासा हुआ तीसरी वार्षिक कोयला बनाम रिन्यूएबल वित्तीय विश्लेषण 2019 रिपोर्ट में। रिपोर्ट की मानें तो 2018 की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों से कोयले की फंडिंग में 126% की गिरावट पाई गई है।

सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी (डाअ/सीएफए) और क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट भारत में 43 कोयला-आधारित और रिन्यूएबल ऊर्जा परियोजनाओं के 50 प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन प्रोपोसल्स पर पर आधारित है। रिपोर्ट कहती है कि कोयला परियोजनाओं के राज्य के स्वामित्व वाले वित्तपोषण में भी महत्वपूर्ण गिरावट आई है। कोयला परियोजनाओं के राज्य के स्वामित्व वाले वित्तपोषण में भी महत्वपूर्ण गिरावट आई है। रिन्यूएबल ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण देने में 6% ड्ड (साल दर साल) का मामूली संकुचन देखा गया, हालांकि इसने ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल ऋण का 95% प्राप्त किया।

CFA (सीएफए) के कार्यकारी निदेशक जो अथियाली ने कहा, "कोयले के लिए परियोजना वित्त में एक महत्वपूर्ण गिरावट का मतलब है कि वित्तीय संस्थानों को कोयले में निवेश से जुड़े वित्तीय और प्रतिष्ठित जोखिम का एहसास होने लगा है। हमारे नीति निर्माताओं को दीवार पर लेखन को पढ़ने की आवश्यकता है। भारत और विदेशों में असमान कोयला परियोजनाओं के वित्तपोषण में स्वस्थ वाणिज्यिक बैंकों को धक्का देने से केवल वित्तीय क्षेत्र में अधिक तनाव पैदा होगा।''

2019 में दो कोयला परियोजनाओं (कुल 3.06GW की क्षमता) को परियोजना वित्त में 1100 करोड़ (US $190 मिलियन) प्राप्त हुआ। 2018 में, 3.8GW की संयुक्त क्षमता वाली पांच कोयला-आधारित परियोजनाओं को, 6081 करोड़ (यूएस $ 850 मिलियन) प्राप्त हुआ। इसके विपरीत, 2017 में 17GW की कोयला परियोजनाओं को 67 60,767 करोड़ (यूएस $ 9.35 बिलियन) उधार दिया गया था।

2019 में कोयले के कुल ऋण में से, 700 करोड़ राजस्थान में खरह (जेएस–ाडब्ल्यू) एनर्जी के बारमेर पावर प्लांट के पुनर्वित्त की ओर गया। बारमेर परियोजना भी 2018 में पुनर्वित्त की गई थी। परियोजनाओं का पुनर्वित्त लगभग हमेशा ब्याज दरों या परिपक्वता तिथि जैसी टर्म शर्तों को बदलने के लिए होता है। खरह एनर्जी प्रगतिशील निजी बिजली उत्पादन कंपनियों में से एक है जिसने नए कोयला बिजली संयंत्रों के निर्माण पर स्थगन की घोषणा की और अपने रिन्यूएबल ऊर्जा पोर्टफोलियो के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया।

शेष 400cr (यूएस $ 91 मिलियन) बिहार के बाढ़ में NTPC (एनटीपीसी) की नई कोयला परियोजना के वित्तपोषण की ओर गया। परियोजना की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण की जिम्मेदारियों को दूसन (Doosan) हैवी इंडस्ट्रीज को प्रदान किया गया है। NTPC (एनटीपीसी), भारत का सबसे बड़ा कोयला बिजली ऑपरेटर, ने हाल ही में नए ग्रीनफील्ड कोयला बिजली संयंत्रों के निर्माण पर स्थगन की घोषणा की।

''निजी और सार्वजनिक रूप से स्वामित्व वाली कोयला बिजली कंपनियों के अलावा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे भारी औद्योगिक राज्यों ने भी एक 'नो कोल' (कोयला को ना) नीति की घोषणा की है। कोयले की अधिकता की समस्या के कारण, और रिन्यूएबल्स की घटती लागत की वजह से भी, इन नीतियों की घोषणा की जा रही है। और यह स्पष्ट रूप से भारत की आर्थिक स्थिरता और विकासात्मक जरूरतों के हित में है,'' आरती खोसला, निदेशक, क्लाइमेट ट्रेंड्स, ने कहा।

41 अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं (5.15GW की कुल क्षमता) को 22,971 करोड़ (US$3220 मिलियन) का संचयी प्राप्त हुआ। 2018 की तुलना में पवन ऊर्जा को उधार 30% गिरा, जबकि सौर उधार में 10% की वृद्धि हुई। 2017, 2018 और 2019 में रिन्यूएबल ऊर्जा के लिए सौर का परियोजना वित्त ऋण पर प्रभुत्व रहा। लेकिन, भारत की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) में वित्तीय तनाव के कारण रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्र में निवेश प्रभावित हुआ है। डिस्कॉम्स 116,340 करोड़ (यूएस $ 16 बिलियन) के लिए जेनेरशन कंपनियों की कर्ज़दार हैं, जिसमें से यूएस $ 1.1 बिलियन रिन्यूएबल ऊर्जा जेनेटर्स के स्वामित्व में है।

''हालांकि भारत अपनी पेरिस जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर है, अगर इसके डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं होता है तो 2030 तक 450GW का इसका महत्वाकांक्षी घरेलू लक्ष्य पीड़ित हो सकता है। पुराने, अकुशल और महंगे कोयला बिजली संयंत्रों को बंद करना और उन्हें रिन्यूएबल ऊर्जा से बदलना सेक्टर के भीतर वित्तीय तनाव को कम करने का एक तरीका हो सकता है,'' आरती खोसला ने जोड़ा।

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, 20 साल या उससे अधिक पुराने कोयला संयंत्रों को बंद करने से विभिन्न डिस्कॉमों के लिए पांच साल में 53,000 करोड़ (7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की बचत हो सकती है। **क्लाइमेट कहानी द्वारा प्रेषित**

विलुप्त होने से बचाया जा सकता है कई प्रजातियों को

एजेंसियां

एक नए अध्ययन में कहा गया है कि 102 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है, यदि समय रहते कार्रवाई की जाय तो इन प्रजातियों को बचाया जा सकता है।

यह मानव इतिहास में पहली बार है जब दुनिया की आधी से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जहां 2030 तक 500 करोड़ से अधिक लोगों के बसने की उम्मीद है। बढ़ती मानव आबादी जैविक विविधता वाले क्षेत्रों में रहते हैं और लगातार विस्तार के कारण जीवों के निवास स्थान को खतरे में डालते हैं, जिससे जैवविविधता विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है और इससे छठे बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का संकेत मिलता है।

दुनिया के अधिकांश बड़े शहर तटीय क्षेत्रों में बसे हैं, जिनमें 70 फीसदी से अधिक का निर्माण नदियों, समुद्र के किनारे पर हुआ है। जिसने तटीय क्षेत्रों की जैवविविधता को प्रभावित किया है।एक नए अध्ययन में कहा गया है कि 102 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। यदि समय रहते कार्रवाई की जाय तो इन प्रजातियों को बचाया जा सकता है। यह जगह ब्रिटिश कोलंबिया में फ्रेजर नदी का मुहाना है जहां इन प्रजातियों का निवास स्थान है।

यूनिवर्सिटी ऑफ़ ब्रिटिश कोलंबिया (यूबीसी) में संरक्षण विज्ञान के एक प्रोफेसर कहते हैं कि वर्तमान में उन्हें बचाने के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। अगर हम जल्दी से कार्रवाई नहीं करते हैं, तो सैल्मन और दक्षिण निवासी व्हेल सहित कई अन्य प्रजातियों के अगले 25 वर्षों में विलुप्त होने की आशंका है।

फ्रेजर मुहाना उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तट पर सबसे बड़ा क्षेत्र है। ब्रिटिश कोलंबिया के निचले मुख्य भूभाग में 30 लाख से अधिक लोग फ्रेजर नदी के पास रहते हैं। उनमें से कई अपनी आजीविका, संस्कृति और कल्याण के लिए इन प्रजातियों और पारिस्थितिकी प्रणालियों पर भरोसा करते हैं। मार्टिन और उनकी टीम द्वारा विकसित प्रायोरिटी थ्रेट मैनेजमेंट नामक संरक्षण फ्रेमवर्क को लागू करते हुए, अध्ययनकर्ताओं ने पारिस्थितिकीय और प्रजातियों के प्रबंधन के लिए 65 से अधिक विशेषज्ञों को जोड़ा है, जो संरक्षण कार्यों की पहचान करने के लिए फ्रेज़र नदी के मुहाने का उपयोग करते हैं, प्रजातियों का पुनः विकास करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह अध्ययन कन्सेर्वटिव साइंस एंड प्रैक्टिस में प्रकाशित हुआ है। इस योजना में एक पर्यावरण प्रशासन निकाय का कार्यान्वयन शामिल है, जो इन रणनीतियों को लागू करने के लिए नगर पालिकाओं, गैर सरकारी संगठनों और उद्योग के साथ मिलकर काम करते हैं। शोध में पाया गया है कि सह-शासन प्रबंधन रणनीतियों को बढ़ाकर, शहरी क्षेत्रों में संरक्षण की सफलता को बढ़ाया जा सकता है।

आज लोग उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में बस गए हैं। ये क्षेत्र जैव-विविधता के साथ हमारे सबसे बड़े शहरी केंद्रों का घर हैं। जहां से जैव-विविधता के लिए अधिकतर खतरे बढ़ रहे हैं। विक्टोरिया विश्वविद्यालय और यूबीसी विश्वविद्यालय में पोस्ट-डॉक्टरल फेलो के रूप में काम करने वाले लौरा केहो का कहना है कि अगर हम अभी से कार्य करना शुरू करते हैं तो इन प्रजातियों को बचाने में अभी भी बहुत देर नहीं हुई है।

केवल 25 सालों तक 38.1 करोड़ (381 मिलियन) डॉलर की कमाई या इसको हमेशा बनाए रखहने के लिए 1.5 करोड़ (15 मिलियन) डॉलर जो जलीय जीवों के स्थान की बहाली और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक भूमि प्रबंधन के लिए परिवहन नियमन से लेकर रणनीतियों में निवेश करना हैं।

अध्ययनकर्ता ने माना कि ऐसे क्षेत्रों के भीतर प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रबंधन रणनीतियों की पहचान करना, और उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रभावी शासन सुनिश्चित करने में भारी चुनौतियां हैं।मार्टिन ने कहा कि केवल हम इस क्षेत्र से इन प्रजातियों को विलुप्त होने के खतरे उठाते हैं, बल्कि इन संरक्षण कार्यों में निवेश करने का लाभ बहुत बड़ा है जिसे भी हम खो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक रूप से 25 वर्षों के लिए 40 से अधिक पूर्णकालिक नौकरियां पैदा करने के साथ, एक फ्रेजर सैल्मन मछली का मूल्य प्रति वर्ष 38.1 करोड़ (381 मिलियन) डॉलर से अधिक है, और व्हेल देखने के लिए आने वाले लोगों से 2.6 करोड़ (26 मिलियन) डॉलर से अधिक है। यदि इन प्रजातियों की संपन्न आबादी का नुकसान हो जाता हैं, तो हम इन उद्योगों को भी खो देगें। हमारा अध्ययन बताता है कि संरक्षण में निवेश से रोजगार और आर्थिक अवसर पैदा होते हैं।

अध्ययन में पाया गया कि भविष्य के प्रमुख औद्योगिक विकास, जिसमें विवादास्पद ट्रांस माउंटेन पाइप लाइन और रॉबर्ट्स बैंक पोर्ट टर्मिनल विस्तार शामिल हैं, दक्षिणी रेजिडेंट किलर व्हेल, सैल्मन और स्टर्जन और प्रवासी पश्चिमी सैंडपाइपर सहित इन प्रजातियों में से कई के भविष्य को खतरे में डालते हैं।अध्ययन में निष्कर्ष है कि दुनिया भर में जैव विविधता संरक्षण के लिए तत्काल रणनीतिक योजना, इस पर ध्यान देने और बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है।

अंततः सबों को अपनाना ही हो गा जैविक खेती

जैविक खेती, की विधि रासायनिक खेती की विधि की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है अर्थात जैविक खेती मृदा की उर्वरता एवं कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती की विधि और भी अधिक लाभदायक है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है इसके साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं। जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यन्त लाभदायक है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए नितान्त आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित न हों, शुद्ध वातावरण रहे एवं पौष्टिक आहार मिलता रहे, इसके लिये हमें जैविक खेती की कृषि पद्धतियाँ को अपनाना होगा जोकि हमारे नैसर्गिक संसाधनों एवं मानवीय पर्यावरण को प्रदूषित किये बगैर समस्त जनमानस को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकेगी तथा हमें खुशहाल जीने की राह दिखा सकेगी।

पौधों में अधिक विविधता होने से कीटनाशकों का उपयोग हो जाता है कम : शोध

एजेंसियां

शोध में पता चला है कि बढ़ती जैव विविधता से कृषि प्रणाली में कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में मदद मिल सकती है। पौधों की बढ़ती विविधता घास के मैदानों में कीटों को प्राकृतिक तौर से नियंत्रण को बढ़ाती है। यह जर्मन सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव बायोडायवर्सिटी रिसर्च के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पता लगाया है। उन्होंने दो प्रयोग कर इस बात को सिद्ध किया है। शोध बताता हैं कि बढ़ती जैव विविधता से कृषि प्रणाली में कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में मदद मिल सकती है।

पृथ्वी पर सभी प्रजातियों की जैविक विविधता, परस्पर प्रभाव और प्राकृतिक घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र, उसके कार्यों और सेवाओं को प्रदान करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि को बढ़ाकर दुनिया की बढ़ती आबादी के लिए भोजन की मांग को पूरा करने के साथ, इन घास के मैदानों पर भी दबाव पड़ रहा है। दुनिया भर में शाकाहारी कीटों से फसल उत्पादन को अनुमानित 18-26 फीसदी का नुकसान हो रहा है, जिसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले महंगे कीटनाशकों के उपयोग में वृद्धि करने को मजबूर किया है। यह शोध साइंस एडवांस में प्रकाशित किया गया है।

पौधों की बढ़ती विविधता से उन पर शाकाहारी कीटों के प्रभाव को स्वाभाविक रूप से कम किया जा सकता है या नहीं, इसकी जांच के लिए जर्मन सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव बायोडायवर्सिटी रिसर्च, लीपज़िग यूनिवर्सिटी और फ्रेडरिक शिलर यूनिवर्सिटी जेना के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने शोध किया। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में दो लंबे समय तक चलने वाले चारागाहों में जैव विविधता प्रयोगों का उपयोग तथा जर्मनी में जेना प्रयोग और मिनेसोटा (अमेरिका) में देवदार क्रीक जैव विविधता प्रयोग किया गया। दो वर्षों के दौरान वैज्ञानिकों ने इन दो प्रयोगों से आंकड़े एकत्र किए, जो मोनोकल्चर (एक ही फसल की खेती) और अलग-अलग प्रजातियों के घास के मैदानों की खाद्य संरचना में गहरी जानकारी प्रदान करते हैं। यूएल में प्रोफेसर निको ईसेनहौअर ने कहा इन दो दीर्घकालीन प्रयोगों से जानकारी प्राप्त हुई है, जो जैव विविधता के महत्व पर प्रकाश डालता है।

विभिन्न प्रजाति के पौधे शाकाहारी कीटों के लिए कम आकर्षक होते हैं

शोधकर्ताओं ने पाया कि पौधों में अधिक विविधता होने से शाकाहारी कीट उन्हें काफी कम नुकसान पहुंचाते हैं। अधिक विविधता वाले मिश्रणों में, शाकाहारी कीटों के पौधों को प्रति ग्राम खाने की दर मोनोकल्चर (एक ही फसल की खेती) की तुलना में 44 फीसदी कम थी। एंड्रयू बार्न्स ने कहा इसका मतलब है कि जहां कई प्रजातियों को एक साथ लगाया जाता है, इससे प्रति वर्ग मीटर में अधिक पौधे विकसित होंगे, और विविध मिश्रणों में प्रत्येक पौधे को शाकाहारी कीटों से कम नुकसान होगा।

पौधों की अधिक विविधता के कारण शाकाहारी कीटों के पास अपने पसंदीदा पौधों की प्रजातियों तक पहुंच की संभावना कम होती है। जिससे उनके यहां बने रहने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा पौधों की अधिक विविधता में ऊतक प्रोटीन (नाइट्रोजन) के निम्न स्तर को दिखाया, जिससे ये पौधे शाकाहारी कीटों के लिए कम पौष्टिक होते हैं।

पौधों की विविधता में वृद्धि के कई सकारात्मक प्रभाव हैं

मोनोकल्चर की तुलना में, अधिक-विविधता वाले पौधे अधिक घास या फसल का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा पौधों की विविधता शाकाहारी कीटों के लिए एक दोहरी समस्या पैदा करते हैं जैसे- कीटों की ओर अधिक शिकारियों का आकर्षित होना और कीटों का कम पसंदीदा भोजन - जो प्राकृतिक रूप से शाकाहारी कीटों के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है।

पौधों की जैव विविधता शाकाहारी कीटों के प्रकोप को सीमित कर सकती है

शाकाहारी कीटों के हानिकारक प्रभाव तथा कीटों पर नियंत्रण करने के लिए कीटनाशकों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। कीटनाशक हानीकारक कीटों को मारने के साथ लाभ पहुंचाने वाले कीटों को भी खत्म कर सकता है। कीटनाशकों के अधिक उपयोग से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। एंड्रयू बार्न्स ने कहा हमारे प्रयोगों से पता चलता है कि पौधों की विविधता को संरक्षित करने से शाकाहारी कीटों को नियंत्रित करने के कई लाभ होते हैं, जो कि कीटनाशकों (एग्रोकेमिकल्स) के उपयोग को कम करने और पौधों की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। निको ईसेनहुअर ने कहा अंततः यह अध्ययन दर्शाता है कि जैव विविधता का समर्थन पारिस्थितिक तंत्र के स्थायी प्रबंधन और लोगों को लाभ प्रदान कर सकता है।

मजे के लिये उड़ाये गुब्बारों से भी जानवरों की हो रही है मौत

एजेंसियां : कई मौकों को आनंदमय बनाने के लिये हम बड़ी संख्या में गुब्बारे उड़ाते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि ये गुब्बारे स्वर्ग में हमारा संदेश लेकर जाते हैं। लेकिन वे हकीकत में समुद्र में उतरते हैं और समुद्री कछुओं को मारते हैं, डॉल्फ़िनि और व्हेल को मारते हैं, और रिबन पक्षियों को उलझाते हैं। कई बार, वे समुद्र तट पर कूड़े के रूप में एकत्र हो जाते हैं। यहां तक कि "बायोडिग्रेडेबल" के रूप में चिह्नित किए गए जानवर जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं । समुद्र से बहुत दूर के जानवर, जैसे कि घोड़े, जब वे अपने घास में उतरते हैं या उन्हें खा जाते हैं तो उन्हें भी बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ये गुब्बारे बिजली के लाइनों में उलझ जाते हैं जिससे कुछ गुब्बारों में आग लग गई और यूरोप में तो स्काई लालटेन ने घरों, बिजली लाइनों, पेड़ों और इमारतों को आग लगा दी है। स्काई लालटेन किसी जानवर तक को भी नुकसान पहुंचा सकती है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए संचालन प्रक्रिया किया जारी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया कि राशन की ऑनलाइन खरीद या घर तक पहुंचाने की सुविधा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और कम भीड़भाड़ वाले समयों में खरीदारी करने वाले लोगों को प्रोत्साहित या छूट देने पर भी विचार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया कि निरुद्ध क्षेत्र में स्थित दुकान बंद रहेंगीं। निरुद्ध क्षेत्र में रहनेवाले दुकानमालिकों और कर्मचारियों को बाजार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सांभर पक्षी त्रासदी: घोषणाओं, वादों के तले दबा बेजुबान पक्षियों की मौत का शोर

पिछले साल नवंबर माह में सांभर झील में एवियन बोट्यूलिज्म बीमारी से 25 से ज्यादा प्रजातियों के लगभग 30 हजार पक्षियों की मौत हो गई थी

सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की मौत को एक साल पूरा हो गया है। पिछले साल नवंबर माह में सांभर झील में एवियन बोट्यूलिज्म बीमारी से 25 से ज्यादा प्रजातियों के लगभग 30 हजार पक्षियों की मौत हो गई थी। जिसके बाद राजस्थान हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। एक साल बाद भी मामले की कोर्ट में सुनवाई जारी है। अब तक नौ सुनवाई कोर्ट में हो चुकी हैं। लेकिन यह बात हैरान करने वाली है कि एवियन बोट्यूलिज्म बीमारी के बारे में राज्य सरकार ने ना तो रिसर्च कराई और ना ही इस तरह की बीमारियों को जांचने के लिए किसी लैब या इंस्टीट्यूट खोलने पर विचार किया गया।

ऐसे इंस्टीट्यूट्स या लैब की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि सांभर त्रासदी के वक्त काफी समय सैंपल भेजने और उनकी रिपोर्ट्स आने में लगा। इससे बचाव और राहत कार्यों में देरी हुई। पिछले साल मृत पक्षियों की मौत का कारण जानने के लिए राजस्थान सरकार ने बरेली की भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्था, भोपाल की राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान, देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान और बीकानेर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनीमल साइंस में सेंपल भेजे थे। सैंपल भेजने और उसकी रिपोर्ट आने में ही कई दिन बर्बाद हुए। ऐसे में सभी संसाधनों के होते हुए भी राजस्थान में इस तरह की लैब की जरूरत महसूस हुई, ताकि सांभर जैसी आपदा के वक्त उसके कारणों की तह तक जल्दी पहुंचा जा सके।

पक्षियों की मौत के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनीमल साइंस, बीकानेर से सबसे पहले सांभर पहुंचने वाले प्रोफेसर अनिल कुमार ने इस संबंध में बताया । उन्होंने ही सबसे पहले पक्षियों में बोट्यूलिज्म की पुष्टि की थी। वह कहते हैं, 'सांभर जैसी बड़ी त्रासदी के बाद सरकार का जो रवैया रहा है, वो काफी निराशाजनक है। सभी संबंधित विभागों ने अपनी जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने की कोशिश की। बोट्यूलिज्म जैसे वैक्टीरिया को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर भविष्य में यह वापस आता है तो उसकी तैयारी हमारे पास बिलकुल नहीं है।' वे आगे कहते हैं, 'सांभर त्रासदी ने सरकार को वन्य जीव और प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा का एक बड़ा मौका दिया, लेकिन समय के साथ-साथ उसे सरकार गंवा रही है। राजस्थान के लगभग हर जिले में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। तीन टाइगर सेंचुरी रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हैं। दो रामसर साइट सांभर और केवलादेव घना भी हैं। इसके अलावा जयपुर की मानसागर झील, खींचन, तालछापर, चंदलाई, चंबल नदी सहित कई जगहें हैं जहां बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। साथ ही 32,845 स्क्वायर किमी भू-भाग पर वन हैं। इतना सब होने के बाद भी हम केन्द्र की लैबों के भरोसे हैं। आपदा के वक्त में राज्य को केन्द्र की संस्थाओं के भरोसे ना रहकर आत्मनिर्भर होना चाहिए।'

वन विभाग ने मांगे 37 लाख, सरकार ने दिए सिर्फ 18 लाख रुपए

राजस्थान हाइकोर्ट ने सरकार से सांभर झील में गार्ड, अस्थाई रेस्क्यू सेंटर और पूरी मॉनिटरिंग के आदेश दिए थे। अगली तारीख पर इसकी सुनवाई होनी है, इसीलिए एक साल बाद कोर्ट के दिखाने के लिए वन विभाग ने अब नावां और सांभर के रतन तालाब पर अस्थाई रेस्क्यू सेंटर, एंबुलेंस जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। वन विभाग ने इस काम के लिए राज्य सरकार से 37 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन सरकार ने मात्र 18 लाख रुपए ही जारी किए हैं।

झील की मुख्य समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दिया

पिछले साल हुई पक्षी त्रासदी पर झील की बर्बादी पर सभी पर्यावरण प्रेमियों व अखबरों ने विशेष रिपोर्ट्स की थीं। इन रिपोर्ट्स में बताया गया था कि किस तरह झील में बना रिसोर्ट, अवैध बोरवेल, ब्राइन चोरी, पर्यटन के नाम पर यहां आने वाली प्रवासी पक्षियों के लिए वातावरण खराब किया जा रहा है। एक साल में इन समस्याओं पर वन विभाग, पशु पालन विभाग या सांभर साल्ट लिमिटेड ने ध्यान ही नहीं दिया है। झील में आज भी रिसोर्ट बना हुआ है। अवैध बोरवेल से ब्राइन की चोरी जारी है। झील की जमीन पर प्रभावशाली लोगों का अतिक्रमण है। हाइकोर्ट की ओर से रिपोर्ट बनाने के लिए भेजे वकील नितिन जैन ने अपनी रिपोर्ट में झील के सुधार के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन उनमें से किसी भी सुझाव पर काम नहीं हुआ है। इन सुझावों में झील के आस-पास के दो किमी को बफर जोन घोषित करने, पर्यटन, रिसॉर्ट, चोरी, अतिक्रमण को हटा कर वेटलैंड के नियम लागू करने की सिफारिश की गई थी। नितिन जैन डाउन-टू-अर्थ को बताते हैं, 'सरकार या उसका कोई भी विभाग झील को लेकर बिलकुल भी गंभीर नहीं है। अब सालभर बाद दिखाने के लिए थोड़े संसाधन वहां इकठ्ठे किए जा रहे हैं जबकि मुख्य समस्याओं पर काम नहीं हो रहा। वे आगे कहते हैं, हाइकोर्ट ने सरकार से झील के विकास को लेकर एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, लेकिन सालभर बाद तक राज्य सरकार ने वो कमेटी तक नहीं बनाई है जो झील के विकास और संवर्धन के लिए सुझाव देने वाली थी।' बता दें कि ये कमेटी चार हफ्तों के अंदर कोर्ट को झील के विकास से संबंधित सुझाव देने वाली थी, लेकिन सरकार ने आजतक इसका गठन ही नहीं किया।

नितिन कहते हैं, 'एक साल केस लड़ने के बाद मेरा अनुभव कहता है कि सरकार की झील के सुधार के लिए कोई मंशा ही नहीं है। सभी विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते दिखते हैं।' पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक उम्मेद सिंह का दावा है कि विभाग ने चार सदस्यों के निगरानी दल का गठन किया है। इसके अलावा इस साल दो पशु चिकित्सक और दो पशुधन सहायकों की भी टीम बनाई है जो किसी इमरजेंसी के वक्त काम करेंगे। जो भी हो बेजुबानों के काल बने इस झील पर सरकार ने आंखें मूंद रखी है।

सीसीएल कर्मियों ने 71वां संविधान दिवस मनाया

रांची : माननीय राष्ट्रपति के साथ सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) मुख्यालय, दरभंगा हाउस, रांची में 'संविधान दिवस'' के अंतर्गतमाननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के साथ लाईव टेलिकास्ट (दूरदर्शनपर प्रसारित) के माध्यम से जुड़कर सीसीएल केसीएमडी पी.एम. प्रसाद के साथ निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह, निदेशक (वित्त) एन.के. अग्रवाल, सीवीओ एस.के. सिन्हा सहित सभी कमांड क्षेत्रों के सीसीएल कर्मियों ने भारतीय संविधान की ''उद्देशिका'' को पढ़ा और उसके मूल्यों को आत्मसात करने का प्रण लिया।

संविधान दिवस के अंतर्गत 'परिचर्चा'का आयोजन

अवसर विशेष पर सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस, रांची स्थित 'कन्वेंशन सेन्टर'में 'संविधान दिवस'के अंतर्गत संवैधानिक मूल्यों एवं भारतीय संविधान के मौलिक सिद्धांत (Constitutional Values and Fundamental Principles of Indian Constitution)विषय पर 'परिचर्चा'का आयोजन किया गया।परिचर्चा में विशेष रूप से आमंत्रित पूर्व महाधिवक्ता, झारखंड सरकार एवं वरीय अधिवक्ता अजित कुमार ने परिचर्चा के विषय पर अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने भारतीय संविधान के मूल्यों जैसे समता, न्याय, स्वंतत्रता आदि पर विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान गतिशील है और इसके इस प्रारूप के लिए हम डॉ बी.आर. अम्बेडकर सहित सभी संविधान निर्माताओं के आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस हमें अपने अधिकारों के साथ साथ देश के अपने प्रति कर्तव्यों की भी याद दिलाता है।

इस अवसर पर सीएमडी पी.एम. प्रसाद के साथ निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह, निदेशक (वित्त) एन.के. अग्रवाल, सीवीओ एस.के. सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये 'परिचर्चा'में भाग लिया। परिचर्चा में सभी क्षेत्रों के महाप्रबंधक एवं उनकी टीम ने भी 'वेबिनार'के माध्यम से भाग लिया। सीसीएल के विभागाध्यक्ष जनसम्पर्क, अनुपम कुमार राणा ने यह जानकारी दी।

भुवनेश्वर - नई दिल्ली - भुवनेश्वर ट्रेन(वाया टाटा) राजधानी स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन के स्थान पर सप्ताह में 4 दिन चलेगी

ट्रेन संख्या 02823 भुवनेश्वर – नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन दिनांक 01/12/2020 से प्रतिदिन के स्थान पर सप्ताह में 04 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को भुवनेश्वर से चलेगी। भुवनेश्वर प्रस्थान 09:30 बजे ,टाटानगर आगमन 15:50 बजे प्रस्थान 15:55 बजे, मुरी आगमन 17:58 बजे प्रस्थान 18:00 बजे, बोकारो स्टील सिटी आगमन 19:15 बजे प्रस्थान 19:20 बजे, कोडरमा आगमन 21:36 बजे प्रस्थान 21:38 बजे, गया आगमन 23:03 बजे प्रस्थान 23:06 बजे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आगमन 01:15 बजे प्रस्थान 01:25 बजे, कानपुर आगमन 05:17 बजे प्रस्थान 05:22 बजे एवं नई दिल्ली आगमन 10:45 बजे होगा। ट्रेन संख्या 02824 नई दिल्ली– भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन दिनांक 02/12/2020 से प्रतिदिन के स्थान पर सप्ताह में 04 दिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार एवं शनिवार को नई दिल्ली से चलेगी।

रांची रेल मण्डल पर संविधान दिवस मनाया गया

रांची : 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व रेलवे संजय मोहंती द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत के संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई, पश्चात रांची रेल मण्डल कार्यालय के परिसर में मण्डल रेल प्रबन्धक श्री नीरज अंबष्ठ ने संविधान दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भारत के संविधान के प्रस्तावना की शपथ दिलाई।

प्रस्तावना शपथ के पश्चात मंडल रेल प्रबंधक , अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ्रा), अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन), सभी शाखा अधिकारी, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों ने प्रियम्बल वॉल पर अपने हस्ताक्षर किए । संविधान दिवस के अवसर पर मंडल के सभी कार्यालयों में सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को मौलिक कर्तव्यों की भी शपथ दिलाई गई तथा मंडल पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य एवं संविधान विषय पर वेबीनार, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इस मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ्रा) अजीत सिंह यादव, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) श्री एम एम पंडित, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी सी हेंब्रम, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवनीश, वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक इरशाद गोरी, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी माणिक शंकर, मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी डॉ देवराज बनर्जी एवं अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

भारत में 2000 साल पुराना है चाय पीने का इतिहास

भारत में चाय कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दिन की शुरूआत से लेकर मेहमानों की आव भगत इसी चाय के माध्यम से ही की जाती है। वैसे चाय को भारत में पिछले 2000 सालों से पिया जा रहा है। करीबन 2000 साल पहले बौद्ध भिक्षु चाय की पत्तियों को चबाते थे ताकि वे अपनी तपस्या को आसानी से कर पाएं। इसके बाद 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला चाय का बागान शुरू किया गया। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों में से एक है और इसकी 70 प्रतिशत से अधिक चाय भारत के भीतर ही पी जाती है। भारत के दार्जिलिंग दुनिया में सबसे बेहतरीन चाय बनाने के लिए जाना जाता है, जिसमें एक अनोखा स्वाद और सुगंध होता है। यह क्षेत्र हिमालय के पास स्थित है। दार्जिलिंग में वर्तमान में 87 चाय बागान हैं, जो करीबन 19,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले हैं। इसमें लगभग 52,000 दैनिक श्रमिक वहाँ कार्यरत हैं। मार्च से नवंबर तक प्लकिंग सीजन के दौरान, अतिरिक्त 15,000 प्लकर प्लांटेशन में लगाए जाते हैं।

प्रशिक्षण देने के लिये सीएमपीडीआइ और सीआइपीईटी के बीच करार

रांची : (सीएसआर) के तहत ''सीआईपीईटी के माध्यम से रांची जिले के गांवों से 40 लाभुकों को प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण'' देने के लिए सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) एवं सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। सीएमपीडीआई के अध्यक्ष एस0 सरन तथा सीआईपीईटीः सीएसटीएस के निदेशक ए0के0 राव के बीच इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।

इस अवसर पर सीएमपीडीआई के निदेशक (तकनीकी/ईएस) के0के0 मिश्रा, निदेशक (तकनीकी/सीआरडी) एस0के0 गोमास्ता, महाप्रबंधक (एचआरडी/सीएसआर) आलोक कुमार जबकि सीआईपीईटी की ओर से वरीय तकनीकी अधिकारी बी0 श्रीकर, प्रशासनिक अधिकारी ए0के0 बक्शी एवं प्रशासनिक सहायक शाहनवाज अहमद उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल पर कैंसर रोग की मार

एजेंसियां

रेड रॉट (लाल सड़न) रोग के कारण उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गांव लोनी में रेड रॉट बीमारी के कारण गन्ने की फसल सूख गई है। मुन्ने खान हर साल अपने दो बीघा खेतों में गन्ना लगाते हैं। दो साल पहले उनके खेत में 120 क्विंटल गन्ना हुआ था, लेकिन पिछले साल 80 क्विंटल गन्ना निकल पाया और इस बार केवल 40 क्विंटल गन्ना ही बच पाया, बाकी सब सड़ गया। मुन्ने खान उन गन्ना किसानों में शामिल हैं, जो गन्ने में लगे रोग रेड रॉट (लाल सड़न) के शिकार हुए हैं।

मुन्ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जिले हरदोई के गांव लोनी के हैं। लोनी उन प्रमुख गांवों में शामिल हैं, जिनकी जमीन पर चीनी मिल लगी हैं और इस वजह से गांव के सभी लोग गन्ने की खेती कर रहे हैं। वह अपने खेतों में कई साल से 0238 वैरायटी का गन्ना लगा रहे हैं। इस वैरायटी की वजह से दो साल पहले तक उनकी आमदनी भी बढ़ गई थी, क्योंकि पिछली वैरायटी के मुकाबले इस वैरायटी का गन्ना लगभग दोगुना होता था, लेकिन इस बार इस वैरायटी पर रेड रॉट बीमारी लग गई है। नगला भगवान गांव के किसान सुधीर पाठक 40 बीघा खेतों पर गन्ना लगाते हैं। वह बताते हैं कि 0238 वैरायटी ने गन्ना किसानों की तकदीर बदल दी, लेकिन अब यही वैरायटी मुसीबत बन गई है। जिन खेतों में 70 क्विंटल प्रति बीघा गन्ना होता था, इस साल केवल 20 क्विंटल प्रति बीघा गन्ना निकला है।

हरदोई जिले के गांव लोनी, नगला भगवान, हरियावां, अहमदी और मुंढ़ेर गांव के पास चीनी मिल लगी हुई है। इस कारण लगभग सभी किसान गन्ने की फसल लगाते हैं, लेकिन सभी गांवों में किसानों ने रेड रॉट बीमारी से हुए नुकसान की जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर के वैज्ञानिक अधिकारी सुजीत प्रताप सिंह ने बताया कि रेड रॉट गन्ने की पुरानी बीमारी है, लेकिन इस बार प्रकोप अधिक दिख रहा है। उन्होंने बताया कि उनका अनुमान है कि इस साल पूरे उत्तर प्रदेश में 30 से 40 हजार हेक्टेयर में लगी गन्ने की फसल को रेड रॉट से नुकसान पहुंचा है। राज्य के गन्ना एवं विकास विभाग ने पिछले साल रेड रॉट से 24 हजार हेक्टेयर में गन्ने की फसल का नुकसान का आकलन किया था।

शोध परिषद के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 42 लाख किसान 23 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती करते हैं। किसानों की औसत उपज 79 टन है। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन तेजी से बढ़ा है और इसका श्रेय गन्ने की वैरायटी सीओ 0238 को दिया जाता है। सुजीत प्रताप सिंह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस सीजन में गन्ने के कुल क्षेत्रफल में से 86 फीसदी हिस्से में सीओ 0238 वैरायटी की फसल लगाई गई और इसी वैरायटी पर रेड रॉट बीमारी लगी है। वह कहते हैं कि इस वैरायटी से किसान और चीनी मिल दोनों का फायदा होता है। जहां किसान को अधिक गन्ना मिलता है, वहीं इस वैरायटी की शुगर रिकवरी अच्छी होने के कारण चीनी मिलों को भी फायदा होता है।

क्या हैं रेड रॉट के कारण ?

कई सालों तक लगातार एक ही वैरायटी लगाने के कारण रेड रॉट का प्रकोप होता है। खेत की मिट्टी में फंफूदी बनने के कारण अगर वही वैरायटी दोबारा लगा दी जाती है तो गन्ना रेड रॉट का शिकार हो जाता है। इसलिए गन्ना किसानों को हर साल वैरायटी बदलने की सलाह दी जाती है, लेकिन किसान अधिक गन्ना हासिल करने के लिए वैरायटी नहीं बदलते। वह बताते हैं कि मिट्टी को उपचारित करके रेड रॉट का प्रबंधन किया जा सकता है, लेकिन एक बार गन्ने को यह रोग लग जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए इसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है।

कैसे बढ़ा 0238 वैरायटी का चलन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अनुसार सीओ 0238 को सीओ एलके 8102 और सीओ 775 के क्रॉस से साल 2009 में उत्पन्न किया गया था। सुजीत प्रताप सिंह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2013-14 में इस वैरायटी का चलन शुरू हुआ। उस साल गन्ने के कुल पैदावार क्षेत्रफल में से 3.4 प्रतिशत इलाके में यह वैरायटी लगाई गई। इसके बाद 2014-15 में 8.44 प्रतिशत, 2015-16 में 19.8 प्रतिशत, 2016-17 में 35.47 प्रतिशत, 2017-18 में 52.55 प्रतिशत, 2018-19 में 67.64 प्रतिशत, 2019-20 में 69.02 प्रतिशत और 2020-21 में 86.70 प्रतिशत हिस्से में 0238 वैरायटी का गन्ना लगाया गया।

ऐसे बढ़ा रेड रॉट का प्रकोप

सीओ 0238 वैरायटी में रेड रॉट बीमारी पहली बार 2015-16 में लगी थी, लेकिन तब इसने केवल 5 प्रतिशत फसल को चपेट में लिया था। लेकिन 2016-17 में 40 फीसदी फसल को प्रभावित किया और पिछले साल से 100 फीसदी को अपनी चपेट में ले रहा है।

फोटो न्यूज

मुत्थु मुरूगन : सिर्फ पक्षियों के खाने लिये करते हैं आधे एकड़ में खेती

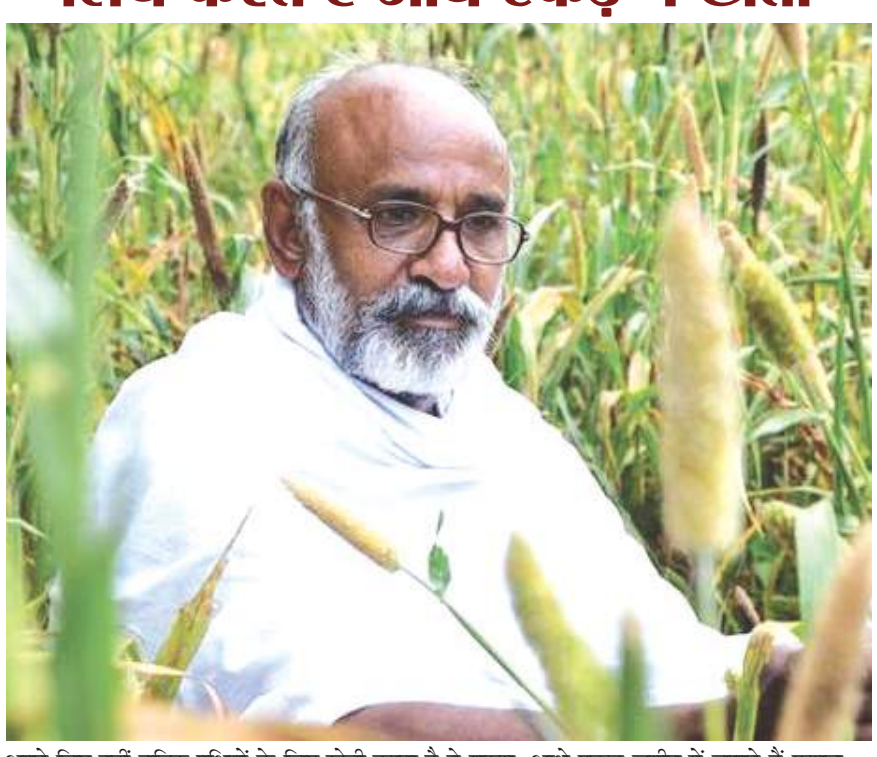

अपने लिए नहीं बल्कि पक्षियों के लिए खेती करता है ये शख्स, आधे एकड़ जमीन में लगाते हैं फसल पक्षियों के लिए खेती करने वाले मुथु अब 62 साल के हैं और वे 1990 से खेती करते आ रहे हैं. उन्होंने अपनी आधा एकड़ जमीन पर सिर्फ पक्षियों के लिए बाजरा और अन्य दाने वाली फसलें लगाई हैं.

इस धरती पर रहने वाले ज्यादातर इंसान सिर्फ अपने और अपने परिवार के हितों के बारे में ही सोचते हैं. हालांकि, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है दुनिया में दूसरों की मदद करने वालों की कोई कमी है. लेकिन, यदि कोई शख्स केवल दूसरों के लिए ही काम करे.. ऐसे व्यक्ति लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक होते हैं. जी हां, आज हम आपको एक ऐसे ही इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए खेतों में पसीना बहाते हैं. खास बात ये है कि उन्हें उनकी मेहनत का कोई मेहनताना भी नहीं मिलता लेकिन जो संतुष्टि, तसल्ली और दुआएं मिलती हैं, शायद वो किसी और को न मिले.

तमिलनाडु के थोंदामुथुर के रहने वाले मुथु मुरुगन न तो अपने लिए खेती करते हैं और न ही किसी दोस्त या रिश्तेदार के लिए करते हैं. मुथु एक ऐसे शख्स हैं जो पक्षियों के लिए खेती करते हैं. जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना. पक्षियों के लिए खेती करने वाले मुथु अब 62 साल के हैं और वे 1990 से खेती करते आ रहे हैं. उन्होंने अपनी आधा एकड़ जमीन पर सिर्फ पक्षियों के लिए बाजरा और अन्य दाने वाली फसलें लगाई हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि मुथु ने कभी भी खेतीबाड़ी में खाद या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया.

रिपोर्ट के मुताबिक मुथु पहले अपने खेतों के किनारे-किनारे ही पक्षियों के लिए फसलें लगाते थे. फिर बाद में वे समय के साथ-साथ आगे बढ़े और अपने आधे खेत में पक्षियों के लिए फसलें लगाना शुरू कर दिए. मुथु ने बताया कि अप्रैल महीने में उन्होंने आधे एकड़ खेत में बाजरा और अन्य चारा लगाया था. करीब एक महीने के बाद फसलें तैयार हो गईं, जिसके बाद उनके खेत में चारा खाने के लिए सैकड़ों पक्षी आने लगे और कुछ समय बाद उनके खेत में लगी सारी फसलें खत्म हो गईं.

मुरुगन ने बताया कि उनके खेतों में चारा खाने के लिए कई दुर्लभ प्रजाति के भी पक्षी आते हैं. पक्षियों को लेकर काफी चिंतित रहने वाले मुथु ने बताया कि हमारे देश में आए दिन शेर, बाघ और हाथी जैसे जानवर भोजन न मिलने की वजह से मर जाते हैं. उन्होंने कहा कि ठीक उसी तरह पक्षियों के बारे में भी सोचना चाहिए. यही वजह है कि उन्होंने पक्षियों के भोजन के लिए अपने खेत में फसलें लगाना शुरू कर दिया.

लॉक डाउन से बस प्रदूषण हुआ कम पर ग्रीनहाउस गैसें लहरा रहीं परचम

निशांत सक्सेना

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) की जारी रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण हुई औद्योगिक मंदी ने ग्रीनहाउस गैसों के रिकॉर्ड स्तर पर कोई अंकुश नहीं लगाया है। ये गैसें, जो वातावरण में गर्मी को बढ़ा रहीं हैं, अधिक चरम मौसम, बर्फ के पिघलने, समुद्र के स्तर में वृद्धि और महासागरीय अम्लीकरण के संचालन के लिए ज़िम्मेदार हैं।

लॉकडाउन ने कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कई प्रदूषकों के उत्सर्जन में तो कटौती की, लेकिन CO2 संद्रता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डब्लूएमओ ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन के अनुसार, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में 2019 में तो वृद्धि बनी ही रही, वो वृद्धि 2020 में भी जारी है। 2019 में CO2 की वृद्धि वार्षिक वैश्विक औसत 410 अंश प्रति मिलियन की महत्वपूर्ण सीमा को पार कर गयी। 1990 के बाद से, कुल रेडिएटिव फोर्सिंग में 45% की वृद्धि हुई है।

अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डब्लूएमओ महासचिव प्रोफेसर पेट्ट्री तालास ने कहा, ''कार्बन डाइऑक्साइड सदियों के लिए वायुमंडल और समुद्र में बस जाता है। पिछली बार पृथ्वी को उड2 की तुलनात्मक एकाग्रता का अनुभव 3-5 मिलियन साल पहले हुआ था, जब तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था और समुद्र का स्तर अब से 10-20 मीटर अधिक था। लेकिन तब धरती पर 7.7 बिलियन लोग नहीं थे। वो आगे कहते हैं, ''हमने 2015 में 400 अंश प्रति मिलियन की वैश्विक सीमा का उल्लंघन किया। और सिर्फ चार साल बाद, हमने 410 पीपीएम को पार कर लिया। इस तरह का वृद्धि दर हमारे रिकॉर्ड के इतिहास में कभी नहीं देखा गया है। लॉकडाउन से उत्सर्जन में आयी गिरावट बस एक छोटी सी चमक भर थी। इसे ह में मेंटेन करना है। पर्यावरण या जलवायु को कोविड-19 महामारी के प्रभावों से किसी तरह का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, यह हमारे औद्योगिक, ऊर्जा और परिवहन प्रणालियों के पूर्ण रूप से पुनरावलोकन और एक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए एक मंच ज़रूर प्रदान करता है। प्रोफेसर पेट्ट्री तालास आगे कहते हैं, ''कई देशों और कंपनियों ने खुद को कार्बन न्यूट्रैलिटी के लिए प्रतिबद्ध किया है और यह स्वागत योग्य कदम है। वैसे भी अब खोने के लिए कोई समय नहीं है।

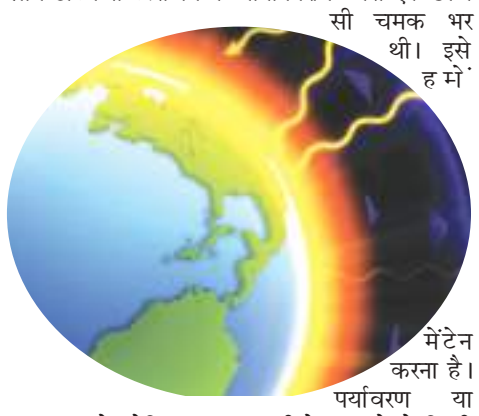

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने अनुमान लगाया कि शटडाउन की सबसे तीव्र अवधि के दौरान, दुनिया भर में दैनिक उड2 उत्सर्जन आबादी के कारावास की वजह से 17% तक कम हुआ है। क्योंकि लॉकडाउन की अवधि और गंभीरता अस्पष्ट हैं, इसलिए 2020 में कुल वार्षिक उत्सर्जन में कमी की भविष्यवाणी बहुत अनिश्चित है।यह ताज़ा रिपोर्ट ग्लोबल एटमॉस्फियर वॉच और पार्टनर नेटवर्क से टिप्पणियों और मापों पर आधारित है, जिसमें दूरस्थ ध्रुवीय (पोलर) क्षेत्रों, ऊंचे पहाड़ों और उष्णकटिबंधीय (ट्रॉपिकल) द्वीपों में वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन शामिल हैं। अब इन गैसों के बारे में अलग अलग बात कर ली जाए। सबसे पहले बात कार्बन डाइऑक्साइड की करें मानव गतिविधियों से संबंधित वायुमंडल में एकल सबसे महत्वपूर्ण लंबे समय तक रहने वाली ग्रीनहाउस गैस है, जो दो तिहाई रेडिएटिवे फोर्सिंग के लिए ज़िम्मेदार है।

दूसरी महत्वपूर्ण गैस है मीथेन, जो लगभग एक दशक के लिए वायुमंडल में बसी रहती है। मीथेन लंबे समय तक रहने वाले ग्रीनहाउस गैसों द्वारा रेडिएटिव फोर्सिंग के लगभग 16% का योगदान देता है। लगभग 40% मीथेन प्राकृतिक स्रोतों (जैसे, आर्द्रभूमि और दीमक) द्वारा वातावरण में उत्सर्जित होती है, और लगभग 60% मानवजनित स्रोतों से आती है (जैसे, जुगाली, चावल की कृषि, जीवाश्म ईंधन का दोहन, लैंडफिल और बायोमास जलाना)। अब बात नाइट्रस ऑक्साइड की करें तो, ये एक ग्रीनहाउस गैस और ओजोन क्षयकारी रसायन, दोनों है। इन सभी गैसों की सांद्रता में फ़िलहाल कोई कमी नहीं आयी है और अंततः इस पूरी रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि सब उतना अच्छा नहीं जितना प्रतीत होता है। जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए अभी करने को बहुत कुछ है।

कुछ कहती है ये तस्वीर पेड़ काटनों से पहले हश्र को भी सोचें

भूजल नीति : खारे पानी की निकासी के लिए उद्योग और परियोजनाओं का शुल्क माफ

एजेंसियां

सीजीडब्ल्यूबी की छूट भू-गर्भ से खारे पानी के निकासी को गति देगा, लेकिन ईकाइयों के जरिए यदि यह खारा पानी बिना योजना के जस का तस बहाया गया तो पर्यावरण को नुकसान भी संभव है। देश में 24 सितंबर, 2020 को भू-जल निकासी नीति को जारी किए जाने के करीब दो महीने बाद अब केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने उन औद्योगिक ईकाइयों, खनन परियोजनाओं और ऐसी सरंचनाएं जो खारा पानी निकालना चाहती हैं, उनके लिए 6 नवंबर, 2020 को गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के मुताबिक ग्राउंड वाटर के तहत खारा पानी निकालने की इच्छा रखने वाली औद्योगिक ईकाइयों को किसी भी तरह का भू-जल दोहन या पुनरुद्धार का शुल्क नहीं देना होगा।

यदि खारे पानी का इस्तेमाल सही से नहीं किया जाता है और डिस्चार्ज बिना शोधन के ही होता है तो यह पर्यावरण के लिए बड़ा संकट है। खासतौर से खारे पानी की वजह से सतह पर काफी नुकसान हो सकता है। खारे पानी की निकासी करने वाली ईकाइयों के लिए छूट में कई शर्तें भी शामिल हैं लेकिन इन पर अमल और निगरानी कैसे होगी यह सवाल अभी अनुत्तरित है। केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण बोर्ड ने 24 सितंबर, 2020 को जारी अपनी गाइडलाइन में कहा था कि भू-जल निकासी के तहत खारे पानी को जमीन के भीतर से निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, हालांकि पर्यावरण प्रदूषित न हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा।

सीजीडब्ल्यूए के मुताबिक 2011 में किए गए ग्राउंट वाटर रिसोर्स के आकलन के मुताबिक कुल 6607 स्थानों (ब्लॉक, मंडल, तालुका, जिले) में से 1071 अति-दोहित, 217 गंभीर और 697 अर्ध-गंभीर व 4580 सुरक्षित स्थान हैं। हालांकि देश में 92 यूनिट्स यानी स्थानों की पहचान ऐसी है जो सेलाइन यानी खारे पानी वाले हैं। ऐसा पानी जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत चालकता (ईसी) 5000 माइक्रोसाइमंस हो वह खारा पानी कहलाता है। भू-गर्भ से खारे पानी की निकासी को लेकर जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी ईकाइयों को उचित प्रवाह (इफ्लुएंट) निपटान योजना तैयार करना होगा ताकि पर्यावरण और आस-पास के क्षेत्रों को नुकसान न हो।

हर्ट अटैक से बचना है तो अच्छी नींद लें

एक नए शोध के अनुसार जिन लोगों को अच्छी तरह से नींद आती है उनमें सहीं से नींद न आने वालों की तुलना में हार्ट फेल होने का खतरा 42 फीसदी कम होता है। स्वस्थ नींद पैटर्न का मतलब सुबह उठना, 7-8 घंटे सोना दिन में सुस्ती न छाना या नींद न आना है।

दुनिया भर में हार्ट फेल हो जाने से 2.6 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होते हैं और मामले बताते हैं कि नींद की समस्याएं हार्ट फेल को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाती है। इस अध्ययन ने स्वस्थ नींद के पैटर्न और हार्ट फेल होने के बीच के संबंधों की जांच की, इसके लिए अध्ययनकर्ताओं ने 2006-2010 तक अस्पताल में नियुक्त किए गए यूके बायोबैंक के 4,08,802 प्रतिभागियों को चुना जिनकी आयु 37 से 73 वर्ष की थी। 1 अप्रैल, 2019 तक हार्ट फेल होने के बारे में जानकारी एकत्र की गई। शोधकर्ताओं ने 10 साल के दौरान हार्ट फेल के औसतन 5,221 मामले दर्ज किए।

शोधकर्ताओं ने नींद की गुणवत्ता के साथ-साथ पूरी नींद के पैटर्न का विश्लेषण किया। नींद की गुणवत्ता के उपायों में नींद की अवधि, अनिद्रा और खर्राटे और नींद से जुड़ी अन्य विशेषताएं

शामिल हैं। महामारी विज्ञान के प्रोफेसर और न्यू ऑरलियन्स में तुलाने ओबेसिटी रिसर्च सेंटर के निदेशक लू आरई ने कहा हमने जो स्वस्थ नींद का स्कोर बनाया वह इन पांच नींद के व्यवहारों के स्कोरिंग पर आधारित था। हमारे निष्कर्ष हार्ट फेल को रोकने में मदद करने के लिए पूरे नींद पैटर्न में सुधार के महत्व को बताते हैं।

नींद के बारे में आंकड़े टचस्क्रीन प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किए गए थे। नींद की अवधि को तीन समूहों में रखा गया था- छोटा, या हर रात में 7 घंटे से कम, 7 से 8 घंटे एक की नींद, और लंबे समय तक या 9 घंटे या उससे अधिक समय तक नींद आना शामिल है। यह अध्ययन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के प्रमुख जर्नल सर्कुलेशन में प्रकाशित हुआ है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दवा के उपयोग, आनुवांशिक विविधताओं के बाद भी स्वास्थ्यप्रद नींद पैटर्न वाले प्रतिभागियों में अस्वास्थ्यकर नींद पैटर्न वाले लोगों की तुलना में हार्ट फेल होने के खतरे में 42 फीसदी की कमी देखी गई। उन्होंने यह भी पाया कि हार्ट फेल का खतरा निम्नलिखित से जुड़ा था :

सवेरे जागने वालों में हार्ट फेल होने का खतरा 8 फीसदी कम था

12 फीसदी खतरा उन लोगों में कम था जो रोजाना 7 से 8 घंटे सोते थे

उन लोगों में 17 फीसदी खतरा कम था जिन लोगों को लगातार अनिद्रा की समस्या नहीं थी

दिन में नींद न आने की रिपोर्ट करने वालों में 34 फीसदी खतरा कम था।

भारत में मलेरिया के मामलों में 60 फीसदी की कमी आई

एजेंसियां

दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली मौतों में 2000-2019 की अवधि में लगातार कमी आई है, 2000 में यह 7,36,000 से 2019 में घट कर 4,09,000 रह गए हैं।दुनिया भर में हर साल 4 लाख से अधिक लोग मलेरिया से मर जाते हैं, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में इसके कारण अनुमानित दो तिहाई मौतें होती हैं।

विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 ने पिछले 2 दशकों में बीमारी के वैश्विक प्रतिक्रिया को समझने में मदद की है। मलेरिया नियंत्रण में अभूतपूर्व सफलता की अवधि जिसमें 150 करोड़ (1.5 बिलियन) मामले और औसतन 76 लाख (7.6 मिलियन) मौतें हुईं। इस रिपोर्ट में मलेरिया और कोविड-19 महामारी के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर में मलेरिया रणनीति 2020 के तहत एक विस्तृत विश्लेषण भी किया है।दुनिया भर के 87 मलेरिया पीड़ित देशों में 2019 में लगभग 22.9 करोड़ (229 मिलियन) मलेरिया के मामले थे, जबकि 2000 में इस-के 23.8 करोड़ (238 मिलियन) मामले थे जिनकी संख्या में गिरावट आई है। मलेरिया के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016ञ2030 के बेसलाइन 2015 में मलेरिया के लगभग 21.8 करोड़ (218 मिलियन) अनुमानित मामले थे।

मलेरिया के मामलों में तीन देश सबसे आगे है, इनमें अनुमानित 99.5 फीसदी मामले हैं, इसमें भारत की सबसे बड़ी हि स्से दारी 87.9 फीसदी है, इसके बाद इंडोनेशिया (10.4 फीसदी) और फिर म्यांमार (1.2 फीसदी) है। दक्षिण एशिया क्षेत्र का सबसे अधिक मलेरिया प्रभावित देश होने के बावजूद, भारत में 2019 में 2017 की तुलना में 60 फीसदी की कमी आई है और 2018 की तुलना में 46 फीसदी की कमी दर्ज की।2019 में इस क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली मौतें घटकर 162 हो गईं जो 2010 की तुलना में 93 फीसदी की कमी है। भारत, इंडोनेशिया और म्यांमार ने क्रमशः क्षेत्र में होने वाली कुल मौतों में 48 फीसदी, 30 फीसदी और 9 फीसदी का हिसाब लगाया। भूटान, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नेपाल और तिमोर-लेस्ते में एक भी मौत नहीं हुई।

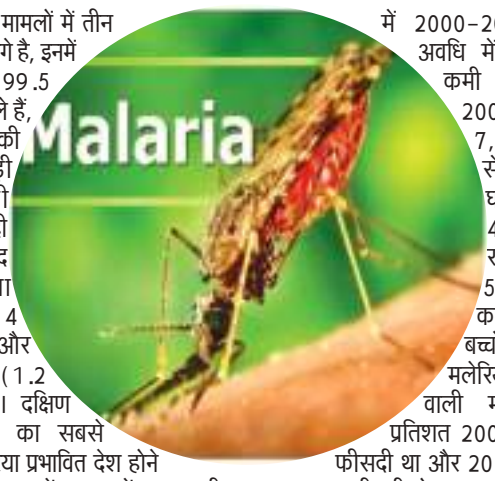

दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली मौतों में 2000-2019 की अवधि में लगातार कमी आई है, 2000 में यह 7,36,000 से 2019 में घट कर 4,090,00 रह गए हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुल मलेरिया से होने वाली मौतों का प्रतिशत 2000 में 84 फीसदी था और 2019 में यह घट कर 67 फीसदी हो गया।

विश्व में मलेरिया से होने वाली लगभग 95 फीसदी मौतें 31 देशों में हुईं। जिनमें नाइजीरिया (23फीसदी), कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य (11 फीसदी), तंजानिया संयुक्त गणराज्य (5फीसदी), मोज़ाम्बिक (4 फीसदी), नाइजर (4फीसदी) बुर्किना फासो (4 फीसदी) शामिल है। 2019 में इन देशों का दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली मौतों का लगभग 51 फीसदी हिस्सा था।

रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया से मृत्यु 44 फीसदी तक कम हुई, जो 2000 में 6,80,000 से 2019 में घटकर 3,84,000 हुई और इसी अवधि में मलेरिया से मृत्यु की दर 67 फीसदी तक कम हो हुई। प्रति 1लाख जनसंख्या पर 121 से 40 मौतें हुई।

दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली मौतों में 74 फीसदी की कमी आई, जो 2000 में 35,000 से 2019 में घटकर 9000 हो गई।

मलेरिया कार्यक्रम और अनुसंधान

जीटीएस ने 2020, 2025 और 2030 के लिए मलेरिया से निजात पाने के लिए आवश्यक धन का अनुमान लगाया है।2016 में कुल वार्षिक संसाधनों का अनुमान 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2020 में 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वैश्विक मलेरिया अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त 0.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।

मलेरिया की रोकथाम

दुनिया भर में मलेरिया पीड़ित देशों के घरों में इससे बचने के लिए छिड़काव किया गया। जनसंख्या का प्रतिशत 2010 में 5 फीसदी से घटकर 2019 में 2 फीसदी हो गया है। दुनिया भर में मलेरिया से लोगों का बचाव करने की संख्या 2010 में 180 मिलियन से घटकर 2015 में 115 मिलियन हुई, 2019 में यह घटकर 97 मिलियन रह गई।

पशु भी करते हैं जीत हार से गर्व एवं हीन भावनाओं का अनुभव

विवेक मिश्र

रिसर्च के नतीजों की मानें तो भविष्य में पशुओं के भीतरी भावों और व्यवहार को और गहराई से जान-समझकर उनके कल्याण वाली अधिक से अधिक योजनाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के स्कूल ऑफ बॉयोलाजिकल साइंस से जुड़े शोधार्थियों की नई थ्योरी यह बता रही है कि जैसे जीत और हार के मौकों पर मनुष्यों के भीतर सकारात्मक या नकारत्मक भाव पैदा होते हैं लगभग वैसी ही भावनाएं पशुओं के जरिए भी संसाधनों के इस्तेमाल की प्रतियोगिता के दौरान अनुभव की जाती हैं। इतना ही नहीं यह भीतरी अनुभव उनके बाहरी और भविष्य के व्यवहार को भी बदल सकता है।

शोध के सार और निष्कर्ष को प्रोसीडिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी जर्नल में प्रकाशित किया गया है।। दरअसल पशुओं के बीच संसाधनों को हासिल करने के लिए होने वाली प्रतियोगिता ही वह शुरुआती बिंदु है जो वैज्ञानिकों को उनके मनोभावों की पड़ताल करने के लिए खींच कर ले गई है। विकास, प्रजनन और टिके रहने के कोशिश में संसाधनों के इस्तेमाल के लिए दो जीवों के बीच आपसी बातचीत ही पशु प्रतियोगिता है, और इस

प्रतियोगता में भावनाएं भी हैं। यह तथ्य है कि संसाधन सीमित होने के कारण प्रतिस्पर्धाएं होती है। साथ ही कुछ ऐसे संसाधन भी हैं, जिनका सभी के लिए एकसमान पहुंच और आपूर्ति भी संभव नहीं है।

अब तक वैज्ञानिक इस बात पर जोर दे रहे थे कि पशु कैसे संसाधनों का और अपने विरोधी की लड़ाई संबंधी क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं लेकिन नया शोध इस बात का तर्क देता है कि पशुओं के मूल्यांकन की यही समझ उन्हें भावनाओं के चरण पर ले जाती है। और आगे यही भावनाएं उनके व्यवहार को भी चलाते हैं।

पशु प्रतियोगिता को एक केस स्टडी के तौर पर शोधार्थियों ने लिया, उन्होंने समझाया कि जैसे एक अवसाद या गुस्से से ग्रस्त व्यक्ति भविष्य को लेकर निराशावादी हो जाता है, उसी तरह से वह जीव जो लड़ाई हार जाते हैं और भी नकारात्मक भाव वाली दशा में पहुंच जाते हैं। वे जहां जीत सकते हैं वहां भी निराशावादी हो जाते हैं, यही वजह है कि भविष्य की लड़ाइयों में भी उनकी इच्छाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं।

बॉयोलाजिकल साइंसेज स्कूल से जुड़े और इस नए पेपर के प्रमुख शोधार्थी एंड्रु क्रंप ने कहा कि मानवीय भावनाएं बगैर संबंध वाली संज्ञान और व्यवहार से प्रभावित होती हैं। मिसाल के तौर पर लोग अपने समूचे जीवन में संतुष्टि के भाव को वर्षा वाले दिनों के बजाए धूप वाले दिनों में अधिक आंकते हैं। हमने पाया कि पशुओं के भाव भी ऐसे ही गैर संबंध वाले संज्ञान और व्यवहार से प्रभावित होते हैं। मिसाल के तौर पर यदि कोई पशु प्रतियोगिता में जीत का अनुभव करते हैं तो वे अधिक सकारात्मक भाव वाले होते हैं और पर्यावरण में ऐसे बहुत कम प्रीडेटर्स की उम्मीद करते हैं। ठीक इसी तरह प्रतियोगिता में हारने का अनुभव करने वाले पशुओं के भीतर नकारात्मकता का भाव होता है और भविष्य में वे दोबारा किसी लड़ाई से कतराते हैं। वहीं, इन प्रभावों के कारण उनमें अधम व्यवहार भी पनप सकता है। जीवन और मौत से जुड़ी ऐसी घटनाएं जो खराब भावनाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं वे आभासी तौर पर निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं, शोधकर्ताओं में डॉ गारेथ एरनॉट कहते हैं कि आम तौर पर पशुओं के व्यवहार का शोध करने वाले आमतौर पर काम में पशुओं के भावनाओं का ख्याल नहीं करते हैं।

हालांकि, इस शोध का निष्कर्ष बताता है कि इससे पशुओं के भावनाओं की भूमिका को स्वीकार करने की जरूरत को बताता है जो कि उनके व्यवहार को समझने मे काफी मददगार हो सकता है। इसकी वजह से पशुओं के कल्याण की योजनाओं पर भी बेहतर काम हो सकता है। उनके नकारात्मक भावनाओं को सकारत्मक भावनाओं में बदलने के लिए उन्हें ढ़ेर सारे मौके दिए जा सकते हैं।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।